भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2336

उत्तर देने की तारीख 03 अगस्त, 2026

12 श्रावण, 1948 (शक)

खेलो भारत नीति और जमीनी स्तर पर खेल विकास

2336. श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री दिलीप शइकीया:
डॉ. भोला सिंह:
श्री ए. राजा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
डॉ. मन्ना लाल रावत:
श्री तेजस्वी सूर्याः
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़ :
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
डॉ. हेमंत विष्णु सवराः
श्री दामोदर अग्रवाल:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री अमर शरदराव काले:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:
श्री अनूप संजय धोत्रे :
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री सुरेश कुमार कश्यपः
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री राजीव प्रताप रूडी:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री सतीश कुमार गौतमः

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री मनोज तिवारी:
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री नव चरण माझी:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री प्रवीण पटेल:
श्री विजय बघेल :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश भर में, राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर पालघर जनजातीय जिले और शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 'खेलो भारत नीति, 2025' का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और यदि हाँ, तो खेलों भारत केंद्रों के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, उपगत व्यय और लाभार्थियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त नीति के तहत जमीनी स्तर के खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने, प्रतिभा की पहचान को सुचारू बनाने और खेल विज्ञान, कोचिंग मानकों तथा एथलीट विकास को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और उक्त जिलों, दरभंगा, अकोला और जलगाँव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश भर में राज्य / संघ राज्यक्षेत्र-वार इस नीति के तहत प्रशिक्षण की स्थिति क्या है;

(ग) एथलीट सहायता, वित्तीय / खेल विज्ञान सहायता, और महिलाओं, ग्रामीण, जनजातीय तथा पैरा-एथलीटों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट उपाय सहित टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के अकोला और पालघर जनजातीय जिले के संबंध में खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), खेल उद्यमिता और स्टार्टअप्स के माध्यम से निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई तंत्र शुरू किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का दरभंगा जैसे क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आधुनिक खेल सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र और खेल अवसंरचना विकसित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त नीति के तहत विशेष रूप से 2032 और 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों और भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के संबंध में प्रमुख लक्ष्यों और परिकल्पित परिणामों का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का उक्त खेलों का समर्थन करने के लिए जलगाँव लोक

सभा निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त खेल अवसंरचना और खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) जी हां। खेलो भारत नीति, 2025 का उद्देश्य भारत में एक सुदृढ़, समावेशी एवं प्रदर्शन-उन्मुख खेल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करना है। इस नीति का कार्यान्वयन केंद्र सरकार अपनी मौजूदा स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से करती है, जिनका संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों एवं प्रतिवेदित रूपरेखा के अंतर्गत किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 03 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील हैं। इसी प्रकार, महाराष्ट्र के पालघर जिले में 01 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) पूर्णतः कार्यशील है। इनका विवरण खेलो इंडिया डैशबोर्ड (https://dashboard.kheloindia.gov.in/) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, कुल 349 खेल अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका विवरण https://mdsd.kheloindia.gov.in/ पर उपलब्ध है।

(ख) खेलो भारत नीति, 2025 के अंतर्गत खेलों के विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ), शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र तथा अन्य हितधारकों के बीच समाभिरूपता के माध्यम से सम्पूर्ण सरकार की रूपरेखा प्रदान की जाती है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था देशभर में कार्यशील 1,066 खेलो इंडिया केंद्रों (केआईसी) के माध्यम से की जाती है। बिहार के दरभंगा में फुटबॉल खेल विधा के लिए 01 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील है, जिसमें 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र के अकोला में मुक्केबाजी खेल विधा के लिए 01 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील है, जिसमें 30 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा महाराष्ट्र के जलगांव में तीरंदाजी खेल विधा के लिए 01 खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील है, जिसमें 37 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जलगांव जिले में बैडमिंटन, निशानेबाजी तथा तैराकी खेल विधाओं के लिए 03 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियां भी कार्यशील हैं।

खेल विज्ञान एवं प्रशिक्षण मानकों को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिवर्ष 6.28 लाख रु. की सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें प्रशिक्षण, खेल विज्ञान संबंधी सहायता, खेल उपकरण, भोजन एवं आवास, बीमा तथा 10,000 रु. प्रतिमाह का आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता शामिल है।

(ग) वर्तमान लॉस एंजिल्स 2028 (एलए 2028) पैरालंपिक चक्र के अंतर्गत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) में कुल 62 पैरा-खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, जिनमें 41 पुरुष तथा 21 महिला खिलाड़ी हैं जबकि पेरिस 2024 पैरालंपिक चक्र के दौरान टीओपीएस के अंतर्गत कुल 59 पैरा-खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की गई थी, जिनमें 40 पुरुष तथा 19 महिला खिलाड़ी शामिल थे।

टीओपीएस के अंतर्गत पैरा खेलों के कोर समूह में शामिल खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप वैयक्तिक सहायता सहित 50,000 रु. प्रतिमाह आउट-ऑफ-पॉकेट भत्ता भी प्रदान किया जाता है। इस सहायता में विदेशों में प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता, खेल-विशिष्ट उपकरण एवं किट, कोचों तथा खेल विज्ञान विशेषज्ञों (जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रशिक्षक तथा आहारविद) का पारिश्रमिक, चिकित्सा सहायता तथा आवश्यकतानुसार प्रोस्थेसिस, व्हीलचेयर एवं अन्य विशेष सहायक यंत्र उपलब्ध कराना शामिल है।

(घ) सरकार खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) जैसी पहलों के माध्यम से खेल पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 18.06.2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए 'खेल गतिविधियों के विकास' की एक साझे सीएसआर थीम के रूप में पहचान की गई है। इसके अंतर्गत खेल अवसंरचना का विकास, खेल उपकरणों की उपलब्धता, पेशेवर प्रशिक्षण तक पहुंच सुनिश्चित करना, खेलों का संवर्धन तथा खिलाड़ियों का पोषण शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र की 46 अकादमियों सहित देशभर में 364 खेलो इंडिया प्रत्यायित अकादमियों को मान्यता प्रदान की गई है। इससे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण एवं विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

(ङ) नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों/अन्य हितधारकों से प्राप्त प्रस्तावों तथा अवसंरचना की उपलब्धता, खेल पारिस्थितिकी तंत्र, प्रतिभा पूल एवं अन्य प्रचालानात्मक मानदंडों की पूर्णता/व्यवहार्यता के आधार पर की जाती है।

खेलो इंडिया स्कीम तथा राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के अंतर्गत खेल अवसंरचना के सृजन एवं उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड (https://mdsd.kheloindia.gov.in) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। वर्तमान में दरभंगा में फुटबॉल खेल विधा के लिए एक खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील है, जिसमें 30 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(च) खेलो भारत नीति का उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान, खेल अवसंरचना, खिलाड़ियों को सहायता तथा खेल प्रशासन को सुदृढ़ बनाकर भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित

करना है, ताकि ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके तथा वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की तैयारियों में सहायता प्रदान की जा सके। वर्तमान में जलगांव में एक खेलो इंडिया केंद्र (केआईसी) कार्यशील है, जिसमें 37 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

*****